महाराष्ट्र राज्य आदि

बनाम

माधावराव दामोदर पाटिलचंद और अन्य आदि

अप्रैल 10, 1968

[एम हिदायतुल्ला, मुख्य न्यायाधीश, जे.सी. शाह, एसएम सीकरी, आरएस बछावत, जी.के मित्तर, सीए वैद्यलिंगम और के.एस हेगड़े, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान, *1950, 1962* का अनुच्छेद *31* बी–महाराष्ट्र अधिनियम *13,* महाराष्ट्र राज्य कृषि भूमि *(*जोतों की सीमा*)* अधिनियम *(1961* का *27)* में संशोधन – *1961* अधिनियम नौवीं अनुसूची में उल्लिखित है, लेकिन कला द्वारा संरक्षित होने पर अधिनियम–संशोधन अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया है , *31* बी – सत्रहवाँ संशोधन, यदि वैध है – सातवीं अनुसूची की सूची *II* की प्रविष्टि *35* – का दायरा – भारत की रक्षा नियमों के तहत पारित आदेश, नियम *125* बी–एलएफ *1961* के महाराष्ट्र अधिनियम *27* की धारा *28* को ओवरराइड करता है।

महाराष्ट्र राज्य कृषि भूमि *(*जोत की अधिकतम सीमा*)* अधिनियम, *1961, 1962* के अधिनियम *13* द्वारा संशोधित, कृषि भूमि की जोत पर एक सीमा लगाकर आम भलाई के लिए कृषि भूमि के वितरण को सुरक्षित करने के लिए पारित किया गया था। अधिनियम की धारा *28,* अन्य बातों के साथ–साथ, कारखानों को गन्ने की आपूर्ति सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने से संबंधित है कि जिन व्यक्तियों को अधिशेष भूमि राज्य सरकार में निहित होने के बाद दी गई है, वे भी उचित मूल्य पर इसकी आपूर्ति करें।

गोदावरी शुगर मिल्स एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी थी, जिसके पास चीनी और संबद्ध प्रीक्वेल के निर्माण के लिए दो कारखाने थे और इसके कारखानों के लिए गन्ने की खेती के उद्देश्य से भूमि का बड़ा क्षेत्र था। अधिनियम के तहत कार्यवाही में मिलों के पास मौजूद भूमि के बड़े क्षेत्रों को अधिशेष घोषित कर दिया गया। अधिनियम की वैधता को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी गई थी: (1) अनुच्छेद 31 बी 1962 के संशोधन अधिनियम 13 को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से नहीं बचाता है, क्योंकि, संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। संविधान (सत्रहवां) संशोधन अधिनियम, 1964, केवल महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोतों की सीमा) अधिनियम, 1961 को शामिल किया गया था, 1962 के संशोधन अधिनियम को नहीं, (2) गोलक नाथ बनाम राज्य में इस न्यायालय के फैसले के बावजूद पंजाब, [1967] 2 एससीआर 762, सत्रहवाँ संशोधन अमान्य है; (3) राज्य विधानमंडल विवादित अधिनियम को अधिनियमित करने में सक्षम नहीं था; और (4) भारत की रक्षा नियमों के नियम 125 बी के तहत राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश, आदेश की अनुसूची में उल्लिखित कारखानों के लिए कुछ क्षेत्रों को आरक्षित करना – जिनमें से एक मिल्स था – और (ए) कुछ शक्तियों के काम पर रोक लगाना कोल्हू, (बी) कलेक्टर द्वारा जारी परमिट के अनुसार आरक्षित क्षेत्रों से गन्ने का निर्यात, और (सी) खांडसारी इकाई द्वारा पेराई या गुड़, गूल या गुड़ के निर्माण के लिए गन्ने की खरीद कलेक्टर द्वारा जारी परमिट के अलावा कोल्हू किसी उत्पादक या गन्ना उत्पादकों के निकाय से संबंधित नहीं है, जो लागू अधिनियम की धारा 28 को अप्रभावी बना देता है।

अभिनिर्धारित किया गया: (I) अनुच्छेद 31 बी की सख्त व्याख्या पर भी किसी अधिनियम को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से बचाने के लिए अनुच्छेद द्वारा निर्धारित एकमात्र आवश्यकता यह है कि अधिनियम को नौवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। आमतौर पर, यदि किसी अधिनियम को उसके शीर्षक से संदर्भित किया जाता है, तो इसका मतलब संदर्भ की तारीख तक इसमें किए गए सभी संशोधनों वाला अधिनियम है, और व्याख्या के इस नियम को नौवीं अनुसूची में लागू न करने का कोई कारण नहीं है। निस्संदेह, कुछ संशोधन अधिनियमों का उल्लेख नौवीं अनुसूची में किया गया है, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से सम्मिलित करने का एकमात्र कारण यह था कि कुछ राज्यों ने अत्यधिक सावधानी बरतते हुए अपने संशोधन अधिनियमों को विशेष रूप से नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी।

श्री राम नारायण बनाम द शिमला बैंकिंग एंड इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड में टिप्पणियाँ, [1956) एससीआर 603, 614, समझाया गया।

(2) गोलकनाथ के मामले में जो परिणाम आया वह यह था कि सत्रहवाँ संशोधन वैध था और यह परिणाम इस न्यायालय की इस पीठ पर बाध्यकारी है।

(3) विवादित अधिनियम, धारा 28 के अलावा, सूची 2 की प्रविष्टि 18 के संबंध में एक कानून है जो 'भूमि आदि' से संबंधित है। और सूची आईडी की प्रविष्टि 42, जो 'संपत्ति के अधिग्रहण और अधिग्रहण' से संबंधित है। अनुभाग। 28 स्वयं सूची II की प्रविष्टि 35 के अंतर्गत आता है जो राज्य में निहित या उसके कब्जे में कार्यों, भूमि और भवनों से संबंधित है, क्योंकि वह खंड केवल उन भूमियों से संबंधित है जो राज्य में निहित हैं। इसलिए, राज्य विधानमंडल अधिनियम पारित करने के लिए सक्षम था।

(4) यदि भारत की रक्षा नियमों के तहत दिया गया कोई आदेश एस के प्रावधानों के विपरीत है। आक्षेपित अधिनियम की धारा 28, आदेश धारा को ओवरराइड कर देगा। लेकिन मौजूदा मामले में राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश इस धारा के विपरीत नहीं था और दोनों एक साथ खड़े हो सकते थे।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1966 की सिविल अपील संख्या 2239 से 2250 तक।

25 अक्टूबर के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील; 1963 में बॉम्बे हाई कोर्ट के विशेष सिविल आवेदन संख्या 970, 884, 692, 963, 959 और 1124 से 1130 तक 1963 और सिविल अपील संख्या 694 1967।

1963 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 1642 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के 9 मार्च, 10, 1965 के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील।

अपीलकर्ता के लिए सी के दफ्तरी, अटॉर्नी–जनरल, एमएसके शास्त्री और एसपी नायर, (1966 के सीए संख्या 2239 से 2250 में)।

उत्तरदाताओं के लिए एफ एस नरीमन, डी एस नार्गोलकर और के आर चौधरी (1966 के सीए संख्या 2239 में)।

आर वी एस मणि, हस्तक्षेपकर्ता संख्या 1 के लिए (1966 के सीए संख्या 2239 में)।

डी पी सिंह, हस्तक्षेपकर्ता संख्या 2 के लिए (1966 के सीए संख्या 2239 में)।

अपीलकर्ताओं के लिए एफ एस नरीमन, भुवनेश कुमारी, ओ सी माथुर, रविंदर नारायण, डी एम पोपट, एस आई ठाकोर और बी भाग "4 सारथी, (1967 के सीए नंबर 694 में)।

सी के दफ्तरी, अटॉर्नी–जनरल और एस पी नायर, उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 के लिए (1967 के सी.ए. संख्या 694 में)।

हस्तक्षेपकर्ता के लिए एस के मेहता (1967 के सीए संख्या 694 में)।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

सीकरी, न्यायधीश .–यह निर्णय 1967 की सिविल अपील संख्या 694 और 1966 की सिविल अपील संख्या 2239–2250 का निपटान करेगा।

सितंबर 1963 में, सिविल अपील संख्या 694/1967 में अपीलकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 (विशेष सिविल आवेदन संख्या 1642/1963) के तहत बंबई उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र राज्य कृषि भूमि की वैधता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की। (होल्डिंग पर सीमा) अधिनियम, 1961 (1961 का महाराष्ट्र अधिनियम XXVII) 1962 के महाराष्ट्र अधिनियम XIII द्वारा संशोधित – इसके बाद इसे विवादित अधिनियम के रूप में जाना जाता है। पहला अपीलकर्ता एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और तालुका में स्थित चीनी और संबद्ध उत्पादों के निर्माण के लिए दो कारखानों का मालिक है।कोपरगांव महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में। प्रथम अपीलकर्ता के पास तालुका के कई गांवों में भूमि के बड़े क्षेत्र भी थे कोपरगांव अपने कारखानों के लिए गन्ने की खेती के उद्देश्य से। आक्षेपित अधिनियम के तहत कार्यवाही में प्रथम अपीलकर्ता के स्वामित्व वाले बड़े क्षेत्रों को अधिशेष घोषित कर दिया गया।

विभिन्न व्यक्तियों ने पहले भी इस अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में इसी तरह की याचिकाएँ दायर की थीं। उच्च न्यायालय ने 25 अक्टूबर, 1963 को अपने फैसले से उनका निपटारा कर दिया। उच्च न्यायालय ने माना कि "महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोतों की सीमा) अधिनियम, 1961, विधायिका का एक वैध हिस्सा है और इसे लागू करना राज्य विधानमंडल की क्षमता के भीतर है, सिवाय इसके कि इसकी धारा 28 के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं और शून्य हैं। हालांकि, हमारे निर्णय का प्रभाव याचिकाकर्ताओं को किसी भी घोषणा प्राप्त करने का अधिकार नहीं देगा कि उनकी भूमि जो एक औद्योगिक उपक्रम के पास है, अधिनियम के संचालन से मुक्त है और न ही पहले प्रतिवादी द्वारा पारित आदेश 28 फरवरी 1963 अमान्य हैं और उनका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। भूमि राज्य में निहित होगी लेकिन वे धारा 28 के किसी भी प्रावधान के तहत भूमि से निपटने के हकदार नहीं होंगे।" उच्च न्यायालय ने उपरोक्त घोषणा के अधीन याचिकाएं खारिज कर दीं। संविधान के अनुच्छेद 132(1) के तहत फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले राज्य ने उपर्युक्त निर्णय के खिलाफ 1966 की अपील संख्या सीए 2239–2250 दायर की।

इस निर्णय के बाद, संविधान को संविधान (सत्रहवें) संशोधन अधिनियम, 1964 द्वारा संशोधित किया गया – जिसे इसके बाद सत्रहवें संशोधन के रूप में जाना जाता है – जो 20 जून, 1964 को लागू हुआ। इस संशोधन में आइटम 21 से 64 के रूप में 44 और अधिनियम शामिल थे, संविधान की नौवीं अनुसूची में. संशोधित अनुसूची में आइटम 34 में लिखा है:

"महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोतों की सीमा) अधिनियम, 1961 (1961 का महाराष्ट्र अधिनियम XXVII)।

1967 की सिविल अपील संख्या 694 (1963 की विशेष सिविल आवेदन संख्या 1642) में अपीलकर्ता की याचिका को 10 मार्च, 1965 के अपने फैसले द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने माना कि सत्रहवें संशोधन ने धारा 28 और अन्य को रखा था विवादित अधिनियम के प्रावधान इस आधार पर चुनौती से परे हैं कि वे किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत थे या उन्हें छीनते या कम करते थे। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि भारत रक्षा अधिनियम, 1962 और उसके तहत बनाए गए नियमों के कारण विवादित अधिनियम निष्क्रिय नहीं हुआ है।

अपीलकर्ताओं ने अनुच्छेद 133(1)(ए) के तहत फिटनेस का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अपील की है।

श्री एफएस नरीमन, जो 1967 की सिविल अपील संख्या 694 में अपीलकर्ताओं के लिए और 1966 की सिविल अपील संख्या 2239–2250 में उत्तरदाताओं के लिए पेश होते हैं, पहले निम्नलिखित बिंदु प्रस्तुत करते हैं:

(1) अनुच्छेद 31 बी मूल रूप से अधिनियमित महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोत की सीमा) अधिनियम, 1961 में संशोधन करने वाले अधिनियमों के प्रावधानों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से नहीं बचाता है:

(2) कि जे सी गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य (') में इस न्यायालय के निर्णय के बावजूद सत्रहवाँ संशोधन अमान्य है;

(3) यह कि राज्य विधानमंडल इस अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए सक्षम नहीं था, जहां तक यह औद्योगिक उपक्रमों द्वारा रखे गए गन्ना खेतों और उन भूमियों को प्रभावित करता है जिन पर गन्ना उगाया जाता है; और

(4) कि भारत रक्षा अधिनियम (1962 का एलआई) और उसके तहत बनाए गए नियम विवादित अधिनियम की प्रभावी धारा 28 को ओवरराइड या प्रस्तुत करते हैं।

हमारे समक्ष उठाए गए बिंदुओं की सराहना करने के लिए, विवादित अधिनियम की योजना पर ध्यान देना और प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करना आवश्यक है।

विवादित अधिनियम की प्रस्तावना मोटे तौर पर अधिनियम का सामान्य उद्देश्य बताती है। यह पढ़ता है :

"जबकि, सामान्य भलाई के लिए कृषि भूमि के सर्वोत्तम वितरण को सुनिश्चित करने के लिए, महाराष्ट्र राज्य में कृषि भूमि की होल्डिंग पर अधिकतम सीमा (या सीलिंग) लगाना सार्वजनिक हित में समीचीन है; सीमा से अधिक धारित भूमि का अधिग्रहण, और उसका भूमिहीनों और अन्य व्यक्तियों को वितरण; और पूर्वोक्त उद्देश्यों से जुड़े मामलों के लिए; यह एतद्द्वारा अधिनियमित है..."

विवादित अधिनियम के प्रावधान भूमि की होल्डिंग (अध्याय II) और अधिशेष भूमि के निर्धारण, घोषणा और निहितार्थ (अध्याय IV) पर सीमा लगाकर इन उद्देश्यों को पूरा करते हैं। अध्याय V मुआवजे के निर्धारण और भुगतान से संबंधित है। अध्याय VI अधिशेष भूमि के वितरण से संबंधित है। अध्याय VII प्रक्रिया और अपील से संबंधित है, और अध्याय VIII में विभिन्न विविध प्रावधान किए गए हैं। हम धारा 21, धारा 27 और धारा 28 को

विस्तार से देख सकते हैं। धारा 21 के तहत कलेक्टर एक घोषणा करता है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ उस भूमि के क्षेत्र, विवरण और पूर्ण विवरण पर अपना निर्णय बताता है जिसे अधिशेष भूमि के रूप में सीमांकित किया गया है। उप–धारा (2) के तहत कलेक्टर इस क्षेत्र को अधिसूचित करता है, और उप–धारा (4) के तहत एक निश्चित समय बीतने के बाद कलेक्टर उस भूमि पर कब्जा कर लेता है जिसे अधिशेष के रूप में सीमांकित किया जाता है। इस प्रकार कब्ज़ा लेने का प्रभाव, संक्षेप में, यह है कि "अधिशेष भूमि को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित माना जाएगा और तदनुसार राज्य सरकार में निहित होगा।" धारा 27 अधिशेष भूमि के वितरण का निर्देश देती है उप–धारा (2), (3), (4) और (5) में निर्धारित प्राथमिकता में, उदाहरण के लिए, उप–धारा (2) एक किरायेदार को प्राथमिकता देती है जिसे भूमिहीन बना दिया गया था क्योंकि जिस व्यक्ति को किसी भी किरायेदारी कानून के तहत व्यक्तिगत खेती के लिए अधिशेष भूमि को अपने किरायेदार से वापस ले लिया गया था। उपधारा (5) प्रदान करती है:

"(5) इसके बाद सभी अधिशेष भूमि (अतिरिक्त भूमि सहित जो उप–धारा (2) या (3) या (4) के तहत नहीं दी गई है, प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में पेश की जाएगी, अर्थात, –

(i) ऐसा व्यक्ति जिससे किसी भूमि को उसके मकान मालिक ने किसी किरायेदारी के तहत निजी खेती के लिए पुनः प्राप्त कर लिया है और जो इसके परिणामस्वरूप भूमिहीन हो गया है, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति उस गांव का निवासी हो जिसमें वितरण के लिए अधिशेष भूमि है स्थित है, या उसके पाँच मील के भीतर;

(i–a) सशस्त्र बलों के सेवारत सदस्य और पूर्व सैनिक;

(i–बी) एक संयुक्त फैनिंग सोसायटी या एक कृषक सोसायटी, जिसके सदस्य निम्नलिखित में से किसी भी विवरण का उत्तर देते हैं, अर्थात्: –

(i) सशस्त्र बलों के सेवारत सदस्य,
(ii) भूतपूर्व सैनिक,
(iii) खेतिहर मजदूर,
(iv) भूमिहीन व्यक्ति, या
(v) छोटे धारक;

बशर्ते कि ऐसी सोसायटी के अधिकांश सदस्य सशस्त्र बलों के सेवारत सदस्य या पूर्व सैनिक हों;

(ii) एक संयुक्त कृषि समिति, जिसके सदस्य निम्नलिखित में से एक या अधिक विवरणों का उत्तर देते हैं, अर्थात्: –

खेतिहर मजदूर या

भूमिहीन व्यक्ति या छोटे धारक;

(iii) एक कृषक समाज, जिसके सदस्य निम्नलिखित में से एक या अधिक विवरणों का उत्तर देते हैं, अर्थात्:·–

खेतिहर मजदूर या

भूमिहीन व्यक्ति या

छोटा धारक;"।

धारा 28 जो विशेष हमले का विषय है, प्रदान करती है:

"28 (1) जहां किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा धारित कोई भी भूमि धारा 21 के तहत राज्य सरकार द्वारा अर्जित की जाती है, और उसमें निहित होती है, ऐसी भूमि वह भूमि है जिसका उपयोग उत्पादन या विनिर्माण या उत्पादन के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जाता है। उपक्रम द्वारा किसी भी सामान, वस्तु या वस्तुओं के मामले में, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखेगी कि भूमि के अधिग्रहण से उपक्रम को भूमि से कच्चे माल के उत्पादन और आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(2) धारा 27 में निहित किसी भी बात के बावजूद, लेकिन इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, उपक्रम को ऐसे कच्चे माल की आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, और आम तौर पर भूमि के पूर्ण और कुशल उपयोग के लिए कृषि एवं उसके कुशल प्रबंधन के लिए राज्य सरकार –

(ए) यदि उस सरकार की राय में यह उपरोक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक है (ऐसी राय उसमें रुचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद बनाई जा रही है) तो एक या अधिक कॉम्पैक्ट ब्लॉकों में इस प्रकार अर्जित क्षेत्र की अखंडता को बनाए रख सकती है; और

(बी) ऐसे नियमों और शर्तों (विशेष रूप से, शर्तों सहित, जो उचित मूल्य पर उपक्रम को कच्चे माल की पूर्ण और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गणना की जाती हैं) के अधीन, भूमि, या उसके किसी भी हिस्से को अनुदान दे सकता है। एक संयुक्त कृषक समिति (या उसका एक सदस्य) जिसमें जहाँ तक संभव हो–

(i) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले ऐसी भूमि उपक्रम को पट्टे पर दी थी,

(ii) उपक्रम द्वारा नियोजित कृषि श्रमिक (यदि कोई हो) !और,

(iii) ऐसी भूमि पर या किसी कच्चे माल के उत्पादन के संबंध में उपक्रम द्वारा लगाया गया तकनीकी या अन्य स्टॉल,

(iv) निकटवर्ती भूमिधारक जो छोटे धारक हैं,

(v) भूमिहीन व्यक्ति :

बशर्ते कि, राज्य सरकार–

(ए) ऐसी अवधि के लिए जो उपरोक्त संयुक्त कृषि समितियों की स्थापना के लिए आवश्यक है, जो कि भूमि पर कब्ज़ा लेने की तारीख से पहली बार में तीन साल से अधिक नहीं होगी (दो साल से अधिक की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ाई जा सकती है)। , निर्देशित करें कि अर्जित भूमि, या उसके किसी भी हिस्से पर, राज्य द्वारा संचालित या प्रबंधित एक या अधिक फार्मों द्वारा, या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले एक या अधिक निगमों (एक कंपनी सहित) द्वारा खेती की जाएगी;

(बी) मकान मालिक को उसके द्वारा उपक्रम को पट्टे पर दी गई अधिशेष भूमि का इतना हिस्सा प्रदान करें, जो उसके द्वारा धारित किसी भी अन्य भूमि के साथ मिलकर छत क्षेत्र से अधिक न हो (लेकिन यदि मकान

मालिक एक सार्वजनिक ट्रस्ट और आय का बड़ा हिस्सा हो) भूमि से शिक्षा या चिकित्सा राहत के प्रयोजनों के लिए विनियोजित किया जा रहा है, संपूर्ण भूमि सार्वजनिक ट्रस्ट को इस शर्त पर प्रदान करें कि मकान मालिक, या जैसा भी मामला हो, सार्वजनिक ट्रस्ट खंड में वर्णित किसी फार्म या निगम को भूमि पट्टे पर दे। (ए) पूर्वोक्त, और उसके बाद, एक जमींदार (सार्वजनिक ट्रस्ट नहीं होने के कारण) के मामले में, वह संयुक्त कृषि सोसायटी का सदस्य बन जाता है, और एक सार्वजनिक ट्रस्ट के मामले में, वह भूमि को एक संयुक्त कृषि सोसायटी को पट्टे पर देता है

(3) राज्य सरकार यह प्रावधान कर सकती है कि, –

(ए) उपधारा (2) के खंड (बी) में निर्दिष्ट किसी शर्त के उल्लंघन के लिए, या

(बी) यदि जमींदार, जिसे जमीन दी गई है, खेत या निगम को जमीन पट्टे पर देने या संयुक्त कृषि सोसायटी का सदस्य बनने में विफल रहता है; या

(सी) यदि वह ऐसी जांच के बाद विचार करता है और जैसा वह उचित समझता है, कि उपक्रम को कच्चे माल का उत्पादन और आपूर्ति उस स्तर पर या उस तरीके से बनाए नहीं रखा गया है, जिसे उचित और कुशल प्रबंधन के साथ बनाए रखा जाना चाहिए, या

(डी) किसी अन्य कारण से भूमि की पूर्ण और कुशल खेती के हित में यह अवांछनीय है कि संयुक्त कृषि समिति को भूमि पर खेती जारी रखनी चाहिए,

अनुदान, समाप्ति की तीन महीने की सूचना देने के बाद और दूसरे पक्ष को कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद, समाप्त कर दिया जाएगा, और भूमि फिर से शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद, राज्य सरकार ऐसी अन्य व्यवस्थाएं कर सकती है जो वह भूमि की उचित खेती और उत्पादन के रखरखाव और उपक्रम को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए उचित समझे।"

अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए पहले बिंदु के संबंध में, हमें ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय यह मानने में सही था कि अनुच्छेद 31 बी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर विवादित अधिनियम को चुनौती से बचाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनुच्छेद 31 बी की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए। लेकिन इसकी कड़ाई से व्याख्या करने पर भी, अनुच्छेद 31 बी द्वारा निर्धारित एकमात्र आवश्यकता यह है कि अधिनियम को नौवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि विवादित अधिनियम को नौवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है या नहीं। यह सच है कि नौवीं अनुसूची की प्रविष्टि 34 में जो उल्लेख किया गया है वह है "महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोत की सीमा) अधिनियम, 1961 (1961 का महाराष्ट्र अधिनियम XXVII)" जिसे मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। और संशोधन अधिनियम, अर्थात् 1962 के महाराष्ट्र अधिनियम XIII का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आम तौर पर यदि किसी अधिनियम को उसके शीर्षक से संदर्भित किया जाता है, तो इसका उद्देश्य उस अधिनियम को संदर्भ की तारीख तक किए गए सभी संशोधनों के साथ संदर्भित करना है। उदाहरण के लिए, संविधान अनुच्छेद 367 में 'सामान्य खंड अधिनियम, 1897' को संदर्भित करता है। यह अनुच्छेद प्रदान करता है कि "जब तक संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो, सामान्य खंड अधिनियम, 1897, उसमें किए जाने वाले किसी भी अनुकूलन और संशोधन के अधीन होगा। अनुच्छेद 372 के तहत, इस संविधान की व्याख्या के लिए आवेदन करें क्योंकि यह भारत के डोमिनियन के विधानमंडल के एक अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू होता है।" यदि अपीलकर्ता के विद्वान

वकील का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि संविधान की व्याख्या के प्रयोजनों के लिए सामान्य खंड अधिनियम, जैसा कि मूल रूप से 1897 में अधिनियमित किया गया था, पर ही विचार किया जाएगा। हम शायद ही कल्पना कर सकते हैं कि संविधान निर्माताओं की मंशा यही थी। इसके अलावा, जब कोई सिविल प्रक्रिया संहिता या आपराधिक प्रक्रिया संहिता या भारतीय दंड संहिता को संदर्भित करता है तो उसका सामान्यतः मतलब होता है कि उन्हें आज तक संशोधित रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि नौवीं अनुसूची की व्याख्या करते समय अधिनियमों को संदर्भित करने के इस सामान्य तरीके को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

यह सच है कि नौवीं अनुसूची में प्रमुख अधिनियमों के अलावा कुछ संशोधन अधिनियमों का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए, मद्रास एस्टेट (उन्मूलन और रैयतवारी में रूपांतरण) अधिनियम, 1948 (मद्रास अधिनियम XXVI, 1948) का उल्लेख आइटम 9 में किया गया है, जबकि मद्रास एस्टेट (उन्मूलन और रैयतवारी में रूपांतरण) संशोधन अधिनियम, 1950 (मद्रास अधिनियम I, 1950)) का उल्लेख आइटम 10 में किया गया है। इसके अलावा आइटम 20 में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल भूमि विकास और योजना अधिनियम, 1948 (1948 का पश्चिम बंगाल अधिनियम XXI) का उल्लेख है, जैसा कि 1951 के पश्चिम बंगाल अधिनियम XXIX द्वारा संशोधित किया गया है। लेकिन फिर भी कई अन्य अधिनियम हैं जिनमें नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने से पहले उनमें संशोधन किया गया था, और हम शायद ही कल्पना कर सकते हैं कि संसद का इरादा केवल मूल रूप से पारित अधिनियमों की रक्षा करना था, न कि नौवीं अनुसूची में उनके शामिल होने की तारीख तक किए गए संशोधनों की रक्षा करना। कुछ संशोधन अधिनियमों को स्पष्ट रूप से सम्मिलित करने का कारण यह प्रतीत होता है कि कुछ राज्यों ने अत्यधिक सावधानी बरतते हुए सिफारिश की है कि उनके संशोधित अधिनियमों को विशेष रूप से नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। यह सच है कि कुछ उद्देश्यों के लिए एक संशोधित अधिनियम अपनी वैयक्तिकता बरकरार रखता है, जैसा कि श्री राम नारायण बनाम द शिमला बैंकिंग एंड इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड (1) में न्यायाधीश जगन्नाधदास ने देखा था:

> "वर्तमान मामले में हम जिस बात से चिंतित हैं वह संशोधन के बाद अधिनियम के किसी विशेष वाक्यांश या प्रावधान का अर्थ नहीं है, बल्कि अधिनियम के बाहर अन्य वैधानिक प्रावधानों के संबंध में संशोधन प्रावधानों का प्रभाव और उन पर प्रभाव है। ऐसे के लिए उद्देश्य यह है कि संशोधन को स्पष्ट रूप से मूल अधिनियम का हिस्सा नहीं माना जा सकता है ताकि इस सिद्धांत को सहायता में बुलाया जा सके कि बाद का अधिनियम पिछले अधिनियम को ओवरराइड करता है।"

हालाँकि, ये टिप्पणियाँ इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती हैं कि जब किसी अधिनियम को उसके शीर्षक से संदर्भित किया जाता है तो इसमें किए गए संशोधनों को शामिल करने का इरादा नहीं है।

तदनुसार, हमें अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा की गई पहली दलील को खारिज कर देना चाहिए और यह मानना चाहिए कि अनुच्छेद 31 बी नौवीं अनुसूची में शामिल होने की तारीख तक इसमें किए गए संशोधनों सहित विवादित अधिनियम की रक्षा करता है। इसलिए, विवादित अधिनियम को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह कला का उल्लंघन करता है। संविधान के 14, 19 और 31. तदनुसार, हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि धारा 28 जिसे मूल रूप से उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना था, अब अनुच्छेद 31 बी के तहत इस आधार पर हमले से संरक्षित है कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

दूसरे बिंदु पर आते हुए, विद्वान वकील ने केवल बिंदु का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि किसी विशेष अनुपात के लिए कोई बहुमत नहीं था क्योंकि पांच न्यायाधीशों ने सत्रहवें संशोधन को शून्य माना क्योंकि यह अनुच्छेद 13 (2) का उल्लंघन था, लेकिन "संभावित ओवररूलिंग" के सिद्धांत को लागू करके उन्होंने घोषणा की कि उनका निर्णय वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। सत्रहवें संशोधन का. दूसरी ओर, हिदायतुल्ला, न्यायाधीश, जैसा कि वह तब थे, ने "संभावित ओवररूलिंग" के सिद्धांत को लागू नहीं किया, लेकिन सत्रहवें संशोधन की धारा 3 (2) को खराब माना। अन्य पाँच न्यायाधीशों ने माना कि सत्रहवाँ संशोधन संविधान का एक वैध संशोधन था। हालाँकि, हम इस न्यायालय द्वारा उस निर्णय में निकाले गए परिणाम से बंधे हैं और यह परिणाम कि सत्रहवाँ संशोधन वैध है, हमारे लिए बाध्यकारी है। हम उल्लेख कर सकते हैं कि हस्तक्षेपकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए श्री मणि ने भी इस मुद्दे को उठाया था लेकिन अंततः उन्होंने मुद्दे को वापस लेने की अनुमति मांगी।

तीसरे बिंदु पर आते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि धारा 28 सूची I की प्रविष्टि 52 के संबंध में एक कानून है, और इसलिए राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे है। प्रविष्टि इस प्रकार है:

> "52. उद्योग, जिनका नियंत्रण संघ द्वारा संसद द्वारा कानून द्वारा सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित किया गया है।"

उनका कहना है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का एलएक्सवी) की अनुसूची में निर्दिष्ट उद्योगों में से एक "चीनी" है। उनका कहना है कि विवादित अधिनियम की धारा 28 का संपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित के संबंध में है: गन्ने का उत्पादन करने वाले औद्योगिक उपक्रमों द्वारा रखी गई भूमि का उद्देश्य गन्ने के उत्पादन और चीनी कारखानों को इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करना था और यह वस्तु पूरी तरह से प्रविष्टि 52, सूची I के अंतर्गत आती है। वैकल्पिक रूप से उनका आग्रह है कि राज्य विधानमंडल के पास प्रतिकूल कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। आइटम 52 के अंतर्गत आने वाले मामलों पर। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विवादित अधिनियम, धारा 28 के अलावा, सूची II की प्रविष्टि 18 और सूची III की प्रविष्टि 42 के संबंध में एक कानून है। ये प्रविष्टियाँ इस प्रकार हैं:

> "प्रविष्टि 18, सूची 2:
>
> भूमि, अर्थात् भूमि में या उस पर अधिकार, भूमि का स्वामित्व, जिसमें मकान मालिक और किरायेदार के संबंध शामिल हैं, और किराए का संग्रह, कृषि भूमि का हस्तांतरण और हस्तांतरण, भूमि सुधार और कृषि ऋण; उपनिवेशीकरण.
>
> प्रविष्टि 42, सूची III :
>
> संपत्ति का अधिग्रहण और मांग।"

यह गंभीर रूप से विवादित नहीं है कि धारा 28 के अलावा शेष विवादित अधिनियम प्रविष्टि 18, सूची II और प्रविष्टि 42 सूची III के संबंध में एक कानून है।

यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या धारा 28 को इस आधार पर कायम रखा जा सकता है कि यह प्रविष्टि 18 सूची II और प्रविष्टि 42, सूची III के तहत बनाए गए जबड़े का एक सहायक या सहायक मामला है, क्योंकि, हमारी राय में, धारा 28 प्रविष्टि के अंतर्गत आती है। 35 सूची II, जिसमें लिखा है:

> "कार्य, भूमि और भवन राज्य में निहित या उसके कब्जे में।"

यह देखा जाएगा कि धारा 28 केवल उन भूमियों से संबंधित है जो राज्य में निहित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि राज्य विधानमंडल राज्य में निहित भूमि से कच्चे माल के उत्पादन और आपूर्ति के संबंध में प्रावधान बनाने और ऐसी भूमि के पूर्ण और कुशल उपयोग और कुशल प्रबंधन के लिए प्रावधान बनाने में सक्षम है।

अब अंतिम बिंदु पर आते हुए, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का आग्रह है कि संविधान के अनुच्छेद 251 के आधार पर धारा 28 अब प्रभावी नहीं हो सकती है क्योंकि यह भारत की रक्षा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रतिकूल है। उनका कहना है कि भारत रक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 3(2)(26) के तहत, केंद्र सरकार "कृषि के नियंत्रण (कृषि भूमि की खेती और उसमें उगाई जाने वाली फसलों सहित)" के लिए आदेश देने में सक्षम है। खाद्यान्न और अन्य आवश्यक कृषि उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से।" 30 अक्टूबर, 1963 की अधिसूचना द्वारा, महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश दिया, जिसके तहत उसने "इससे जुड़ी अनुसूची के कॉलम (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक क्षेत्र को क्रमशः उसके कॉलम (2) में निर्दिष्ट कारखाने के लिए आरक्षित कर दिया", और गन्ने की खरीद और निर्यात के संबंध में अन्य प्रावधान किए। अनुसूची में निम्नलिखित क्षेत्रों को अपीलकर्ता, गोदावरी शुगर मिल्स लिमिटेड के लिए आरक्षित क्षेत्र बनाया गया:

"भीतर शामिल क्षेत्र निम्नलिखित तालुकों की सीमाएँ.

(i)कोपरगांव अहमदनगर जिले के.

(ii) अहमदाबाद जिले का श्रीरामपुर।"

यह आदेश महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत रक्षा नियमों के नियम 125–बी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया था।

विद्वान वकील का कहना सही है कि जिस हद तक भारत की रक्षा नियमों के तहत दिए गए वैध आदेश धारा 28 के प्रावधानों के साथ संघर्ष करते हैं, आदेश विवादित अधिनियम की धारा 28 को खत्म कर देंगे। लेकिन यहां उपलब्ध सामग्री में हमें यह नहीं दिखाया गया है कि 30 अक्टूबर, 1963 का आदेश धारा 28 के विपरीत कैसे है। आदेश पहले अनुसूची में उल्लिखित कारखानों के लिए कुछ क्षेत्रों को आरक्षित करता है, और फिर कुछ के काम करने पर रोक लगाता है। पावर क्रशर और जिले के कलेक्टर द्वारा जारी परमिट के अलावा आरक्षित क्षेत्रों से गन्ने के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह पेराई या विनिर्माण के लिए गन्ने की खरीद पर भी प्रतिबंध लगाता हैवह, गुल या गुड़ द्वारा एक खांड़सारी इकाई या क्रशर द्वारा जो कलेक्टर द्वारा जारी परमिट के तहत और उसके अनुसार गन्ना उत्पादक या उत्पादकों के निकाय से संबंधित नहीं है। धारा 28, अन्य बातों के साथ–साथ, कारखानों को गन्ने की आपूर्ति सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने से संबंधित है कि जिन व्यक्तियों को भूमि दी गई है, वे भी उचित मूल्य पर इसकी आपूर्ति करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि धारा 28 के प्रावधान 30 अक्टूबर 1963 के आदेश के साथ एक साथ खड़े हो सकते हैं। हमारी राय में विद्वान वकील द्वारा उठाए गए बिंदु में कोई बल नहीं है।

परिणामतः सिविल अपील क्रमांक 694 सन् 1967 खारिज कर दी गई। अन्य अपीलों (1966 की सिविल अपील संख्या 2239–2250) की अनुमति है, उच्च न्यायालय के फैसले, जहां तक उसने धारा 28 को शून्य घोषित किया, अलग रखा और जिन याचिकाओं से ये अपीलें उठीं, उन्हें खारिज कर दिया गया। सभी अपीलों में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

वी.पी.एस 1967 का सीए नंबर 694 खारिज, अन्य अपीलें मंजूर।

चंद्रकांत शुक्ल की देखरेख में शशिप्रभा द्वारा अनुवादित।